

कम कीमत पर एथेनॉल बेचने को तैयार चीनी मिलें

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 6 अक्टूबर

चीनी मिलों ने तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) से एथेनॉल की मांगी गई कीमत में 10-15 फीसदी कटौती कर दी है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट से एथेनॉल मिश्रण की व्यवहार्यता कम हो गई है। पहले चीनी मिलें एक्स-डियो कीमत 50 रुपये प्रति लीटर मांग रही थीं, लेकिन अब वे ओएमसी के साथ 44-46 रुपये प्रति लीटर पर सौदेबाजी कर रही हैं। हालांकि यह कीमत पिछली निविदा में ओएमसी द्वारा चुकाई गई कीमत 38-42 रुपये प्रति लीटर से 4-6 रुपये प्रति लीटर ज्यादा है। अगर ओएमसी चीनी मिलों द्वारा मांगी गई कीमत पर राजी होती है तो इससे चीनी मिलों की वित्तीय हालत में सुधार होगा। हालांकि यह मामूली ही होगा। ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन के महानिदेशक वी एन रैना ने कहा, 'फिलहाल बातचीत चल रही है। लेकिन हम पिछली निविदा से ज्यादा कीमत चाहते हैं।'

वहीं कच्चे तेल की कीमतें 19 जून के अपने सर्वोच्च स्तर 115 डॉलर प्रति बैरल से करीब 17 फीसदी गिर गई हैं और ये नायमैक्स में फिलहाल 95.74 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई हैं। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते तेल विपणन कंपनियों ने भी पेट्रोल की कीमतें 5 फीसदी घटा दी हैं और ये मुंबई में 76.14 रुपये प्रति लीटर पर बिक्री कर रही हैं। जबकि 25 जून को पेट्रोल के दाम 80.16 रुपये प्रति लीटर थे।

एक विश्लेषक ने कहा कि चीनी मिलों ने तेल विपणन कंपनियों के लिए एथेनॉल की व्यवहार्यता समझी है। तेल विपणन कंपनियों के लिए 50 रुपये प्रति लीटर पर एथेनॉल खरीदना व्यवहार्य नहीं है, इसलिए चीनी मिलों ने मांग गई कीमत में कटौती की है। चीनी मिलें अब इस बात से संतुष्ट हैं कि तेल विपणन कंपनियों को उनसे एथेनॉल खरीदना ही होगा, क्योंकि ईंधन नीति में हालिया संशोधन के तहत एथेनॉल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर रोक लगाई गई है। रोचक बात यह है कि चीनी मिलों ने पिछली निविदा में आयातित एथेनॉल की आपूर्ति के लिए न्यूनतम कीमत 80 रुपये प्रति लीटर बोली थी।

तेल विपणन कंपनियों के पक्ष में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने अक्टूबर 2014 से शुरू हो रहे

मिलों का रुख पड़ा नरम



- मिलों ने एथेनॉल की मांगी गई कीमत 10-15 फीसदी घटाई
- कच्चे तेल की घटती कीमतों से कटौती के लिए बाध्य
- कच्चे तेल की कीमत हाल के उच्चतम स्तर से 17 फीसदी घटी
- तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत 5 फीसदी घटाई
- मिलें आपूर्ति की प्रतिबद्धता से बच रही हैं, संभवतया बेहतर आमदनी के लिए शीरा/एल्कोहल के लिए बिक्री के लिए
- इस वर्ष भी 5 फीसदी मिश्रण का लक्ष्य हासिल नहीं होगा

आगामी गन्ना पेराई सीजन के दौरान 158 लीटर एथेनॉल खरीदने के लिए निविदा जारी की है। सुत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बड़ी मिलों ने निविदा में भाग लिया, लेकिन उन्होंने आवेदन फॉर्म में मात्रा को लेकर प्रतिबद्धता नहीं जताई है। बड़ी मिलें आगामी सीजन के लिए मात्रा

हो सकती है और उत्पादन में गिरावट की संभावना है।

पिछले साल भारत ने अच्छी आमदनी के लिए करीब 4,80,000 टन शीरे का निर्यात किया था। यह 13 करोड़ लीटर एथेनॉल के उत्पादन के लिए पर्याप्त हो सकता था। इस साल चीनी मिलें सभी विकल्प खुले रखने के लिए सतर्कता बरत रही हैं। 5 फीसदी अनिवार्य मिश्रण का लक्ष्य पूरा करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को हर साल 155 करोड़ लीटर एथेनॉल की जरूरत होगी।

इस साल चीनी का उत्पादन 2.5 करोड़ टन अनुमानित है, इसलिए एल्कोहल (चीनी का उपोत्पाद और एथेनॉल की पूर्व अवस्था) का उत्पादन 250 करोड़ लीटर तक पहुंच सकता है। इसमें 100 करोड़ लीटर की खपत पेय एल्कोहल क्षेत्र में जबकि करीब 70 करोड़ लीटर की खपत रसायन उद्योग में होती है। चीनी मिलें हर साल केवल 80 करोड़ लीटर की आपूर्ति करने में ही सक्षम हो सकती हैं। वर्तमान स्थिति को भांपते हुए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 7 जुलाई को लोक सभा में कहा था कि तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिश्रण केवल 1.37 फीसदी ही कर पाएंगी, जबकि लक्ष्य 5

फीसदी है।

मंत्री ने कहा कि तेल विपणन कंपनियों ने लक्ष्य (5 फीसदी मिश्रण) की बाधाओं का संज्ञान लिया है। एथेनॉल इंडिया डॉट नेट के प्रमुख दीपक देसाई ने कहा कि पिछले साल अगर एथेनॉल की कीमतें ऊंची होती तो देश से शीरे का निर्यात थम सकता था। तेल विपणन कंपनियों को शराब विनिर्माताओं से कड़ी टक्कर मिल रही है। वे रम और व्हिस्की बनाने के लिए कोई भी कीमत चुका सकते हैं। शराब की कीमत में कच्चे माल की लागत महज 10-15 फीसदी होती है। इसलिए शराब विनिर्माता चीनी मिलों से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कीमत चुका सकते हैं। अगर तेल विपणन कंपनियों को एथेनॉल की ज्यादा खरीद करनी है तो उन्हें शराब विनिर्माताओं की तुलना में कीमत बढ़ानी पड़ेगी। रैना ने कहा, 'वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि भारत अधिसूचना के बाद तीन सीजन गुजरने के बाद इस साल भी 5 फीसदी मिश्रण का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा।' 16 लाख टन सरप्लास चीनी से छुटकारा पाने के लिए भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) ने गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने की मंजूरी मांगी है।

विपणन रुख